लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 मई 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -42

"वर्तमान और भविष्य के सुखी जीवन के लिए जरुरी, फसल अवशेष न जलाएं-पर्यावरण बचाएं

: सुविचार

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य आगाज

3

तख्ती और स्कूल बैग की जगह टैबलेट

4

पानी की एक-एक बूंद के सदुपयोग का संकल्प

7

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया

अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र जनता को समर्पित

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विशेष प्रतिनिधि

बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही राज्य सरकार की ओर से अंबाला छावनी में 'अटल कैंसर केयर केंद्र' जनता को समर्पित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, सांसद रतन लाल कटारिया और अन्य कैबिनेट मंत्री व अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस अस्पताल में आधुनिक तकनीक से कैंसर मरीजों का इलाज होगा। झज्जर के बाढ़सा में भी कैंसर का एम्स बना है। जहां कैंसर के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर साल कैंसर के करीब 28 हजार मरीज आते हैं। इन संस्थानों में चिकित्सा की अत्याधुनिक तकनीक मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। कैंसर के संपूर्ण इलाज के लिए दुनिया की नवीनतम तकनीक वाली दो मशीनें पॉसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और सिंगल फोटॉन एमिशन टोमोग्राफी लगाई जानी है, जिनकी लागत 34 करोड़ रुपए है।

उन्होंने कहा कि अंबाला सेंटर से हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों के कैंसर रोगियों का भी उपचार हो सकेगा। इस इस केंद्र में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की सुविधा के लिए 100 लोगों की क्षमता का हॉस्टल भी बनाया जाएगा।

पेंशन का एलान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्टेज थ्री और फोर के कैंसर मरीजों को हरियाणा सरकार द्वारा अढाई हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। थैलेसिमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए भी पेंशन की सुविधा पहले ही की गई है। सरकार द्वारा एड्स के रोगियों को भी पेंशन दी जा रही है।

केयर सेंटर में सुविधाएं

केयर सेंटर में रेडियोथेरेपिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, आरटीटी आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न विशिष्ट पद (सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन फिजिसिस्ट कम आरएसओ, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) और अन्य एचआर सृजित किए गए हैं। इस 'अटल कैंसर केयर केंद्र' में कैंसर रोगियों को ओपीडी, आईपीडी, प्रशामक देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मैमोग्राफी यूनिट चालू की गई है। इस केंद्र में नवीनतम उपकरण जैसे लीनियर एक्सेलेरेटर, ब्रेकीथेरेपी यूनिट, सीटी सिम्युलेटर आदि स्थापित किए गए हैं।

2025 तक बनेंगे मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में 2025 तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। सरकार ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं और भविष्य में भी इन सीटों को बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। जल्द ही प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर के पैमाने को पूरा किया जाएगा।

जेपी नड्डा ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उनकी उपस्थिति में अंबाला छावनी में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह सेंटर उत्तर भारत का प्रमुख कैंसर केयर सेंटर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बधाई के पात्र हैं जिनकी मेहनत से स्वास्थ्य सेवाएं उत्कृष्ट हो रही हैं।

बढ़ते तापमान में लू से बचें

- आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें।
- दोपहर के समय ज्यादा मेहनत के कार्य से बचें,
- जरूरी कार्य से बाहर जाना पड़े तो सूती व ढीले कपड़ों का प्रयोग करें।
- सिर को ढक कर रखें। आंखों के लिए सनग्लासेज का प्रयोग करें।
- शराब, चाय या कॉफी आदि का सेवन न करें।
- सत्तू, दही और छाछ का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
- ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह पर न जाएं, न ही बाहर से आकर तुरंत ए.सी, कूलर चलाएं।
- लू से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें।
- बाहर का खाना तथा गर्म व मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचें।
- धूप से आकर तुरंत हाथ-मुंह न धोयें और न ही पानी पिए, थोड़ा सा इंतजार करें।
- खाना बनाने, परोसने व खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं।
- बाजार में उपलब्ध पेय पदार्थों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।
- गंदे-सड़े, गले व कटे फल और खुले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें।

नोटः हाथ-पैरों में जलन, थकान और शरीर का तापमान बढ़ना लू के लक्षण है। लू लगने की स्थिति में डाक्टर से संपर्क करें। तब तक संबंधित व्यक्ति को तुरंत ठंडक में लिटाएं और कपड़े ढीले कर दें। तलवों में लौकी के रस की मालिश करें अथवा बर्फ की पट्टी रखें। शिकंजी, ग्लूकोज का घोल अथवा शरबत पिलाएं।

डा. प्रवीण मल्हौत्रा पीजीआईएमएस रोहतक

अमृत सरोवर से बदलेगी गांवों की तस्वीर

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगी अमृत सरोवर मिशन योजना

मनोज प्रभाकर

करीब साढ़े तीन दशक पहले तक गांवों के जोहड़ों का पानी पशुओं के लिए अमृत होता था। लोगों के पेयजल के लिए कुएं होते थे, जिनका पानी भी अमृत समान ही होता था। कुएं से पानी खींचने के लिए हर घर में 'नेजू-बाल्टी' होती थीं। पनघट और पनघट पर रमझौल के गीत आज भी गांव की आबोहवा में विद्यमान हैं।

पानी की शुद्धता एवं उपलब्धता को देखते हुए ग्रामीण संस्कृति में तालाब और कुओं को पूजने की परंपरा रही है। विकास की भागमभाग में यह संस्कृति पीछे छूट गई। रहन सहन के तौर तरीके बदल गए।

गांव व शहरों में लगे असंख्य सबमर्सिबल पंपों से भूजल के अनावश्यक दोहन से संतुलन बिगड़ा है। पेयजल व निकासी के पानी के अप्रबंधन की वजह से गांवों के तालाब तालाब नहीं रह गए, गंदे पानी के पोखर में तब्दील हो गए। पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं रहा, ओवरफ्लो की समस्या खड़ी हो गई, वह अलग।

ग्रामीण क्षेत्र की इस गंभीर समस्या के निदान की ओर अभी तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, हो सकता है उनके दिमाग में इसका कोई समाधान ही न आया हो लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने इस परेशानी को बखूबी समझा और निदान के लिए 'अमृत सरोवर योजना' का शुभारंभ कर दिया। हालांकि हरियाणा सरकार पहले ही इस तरह की योजना के तहत प्रदेश के बड़े गांवों के तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर चुकी है।

प्रदेश में 18 हजार तालाब हैं, जिनमें से 4 हजार में सिर्फ़ बरसाती पानी एकत्रित होता है। 6 हजार तालाबों में पशुओं के लिए पानी भरा रहता है और 8 हजार तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। सबसे पहले 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8 हजार तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इनमें से 1,600 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में बचे हुए सभी तालाबों की दशा सुधारी जाएगी। इसके अंतर्गत तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल व सौंदर्यीकरण करके आस-पास के स्थल को भ्रमण योग्य बनाया जाएगा। प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का गठन किया गया है और इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया है।

हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार योजना के तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए जाने हैं। प्रथम चरण में राज्य के सभी 22 जिलों में 1,650 तालाबों को चिह्नित कर लिया गया है, जिसमें 115 शहरी तथा 1,535 ग्रामीण तालाब शामिल है। इन तालाबों का विकास तय मानदंडों जैसे तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ या इससे अधिक होना चाहिए, तालाब की उचित गहराई के साथ-साथ उचित ढलान वाले तटबंध बनाना इत्यादि के अनुसार किया जाएगा।

तालाबों के किनारे बड़, पीपल, नीम आदि प्रकार के वृक्ष व अन्य वनस्पति लगाई जाएगी, ताकि वातावरण व जैव विविधता पर अनुकूल प्रभाव पड़े। तालाब में बहने वाले गंदे पानी को ठीक से उपचारित किया जाएगा ताकि पानी को पशुओं के पीने योग्य, मछली पालन व सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सके और तालाबों के पुर्नद्धार से निरन्तर गिरते भू-जल स्तर को सुधारा जा सके।

संपादकीय

राखीगढ़ी का सत्य

हरियाणा के लिए 'राखीगढ़ी' में हुआ नया उत्खनन गौरव का विषय है। अब पुरातत्व सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरा है कि राखीगढ़ी, मोहेन्जोदाड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता का शहर है। कुछ तथ्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि 3500 ईसा पूर्व भारत में एक पूर्व विकसित सभ्यता थी।

हिसार जिले के गांव राखीगढ़ी में पहली बार 1963 में खुदाई की गई थी और तब इसे सिंधू-सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया था। उस समय के शोधार्थियों ने प्रमाण सहित यह घोषणा की थी कि जमीन में दफ़न यह शहर कभी मोहेन्जोदाड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा रहा होगा। अब तक यही माना जाता रहा है कि पाकिस्तान स्थित हड़प्पा और मोहेन्जोदाड़ो ही सिंधूकालीन सभ्यता के बड़े नगर थे। राखीगढ़ी में खुदाई और शोध का काम एक-एक कर चलता रहा। 1977 से लेकर अब तक चार बार अधिकृत रूप से खुदाई हुई है और जो कुछ भी मिला है, वह सिंधू-सरस्वती सभ्यता को एक खुली और विस्तृत दृष्टि से देखने को मजबूर कर रहा है।

बीच में राखीगढ़ी में उत्खनन का काम बंद भी रहा क्योंकि राजकीय अनुदानों के दुरुपयोग का मामला उछला तो सीबीआई को इसकी जांच करना पड़ी थी। छह वर्ष पहले ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई थी कि कुछ ग्रामीणों और कुछ पुरातत्व तस्करों ने अवैध रूप से कुछ जगह खुदाई की थी और कुछ दुर्लभ अवशेष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचे गए। राखीगढ़ी का पुरातात्विक महत्व विशिष्ट है। इस समय यह क्षेत्र पुरातत्व विशेषज्ञों की दिलचस्पी और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। खुदाई के दौरान हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेषों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इतने वर्ष पहले भी 'टाऊन प्लांनिंग' पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। निःसंदेह एक बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर शहर बसाया गया था। ऐसी कुछ तकनीकों का इस्तेमाल आज हम शहर बसाने के लिए कर रहे हैं।

2014 में भी राखीगढ़ी की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की रेडियो एवं कार्बन डेटिंग के अनुसार इन अवशेषों का संबंध हड़प्पा-पूर्व और प्रौढ़-हड़प्पा काल के अलावा उससे भी हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यता से भी प्राप्त अवशेष इस सभ्यता को लगभग 6500 वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं। सोने-चांदे के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां आदि अनेक वस्तुएं भी मिलीं हैं। अप्रैल 2015 में भी खुदाई के दौरान चार नरकंकाल मिले इनमें तीन की पहचान पुरुष के रूप में और एक ही महिला के रूप में हुई थी। इस बार की खुदाई में भी कई नरकंकाल मिले हैं जिनके नमूने डीएनए जांच के लिए भेज दिए गए हैं। खुदाई का इतिहास बताता है कि प्राचीन सभ्यताओं के साथ लूटमार और छेड़छाड़ भी बहुत की गई। मगर जो भी आज हो रहा है वो यही बताता है कि अविभाजित भारत में चार हजार वर्ष पहले की सभ्यता एवं निर्माण कलाएं पूरी तरह विकसित थी। खुदाई के दौरान मिले सामान से विशेषज्ञों का आकलन है कि यहां कोई बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी रहा होगा। अब सब परतें खुलती जाएंगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हड़प्पाकाल का यह शहर पानी की कमी के चलते विलुप्त हुआ होगा। राखीगढ़ी की विरासत सभ्यता पर गर्व करने का विषय है लेकिन उस काल में या मोहेन्जोदाड़ो-हड़प्पा युग में साहित्य व संगीत का स्वरूप क्या था? यदि शोध यूं ही उत्साह सहित चलता रहा तो निश्चित है कि ये तथ्य भी उभरेंगे।

- डॉ. चन्द्र त्रिखा

जीएसटी संग्रहण में पांचवें नंबर पर हरियाणा

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 9,200 करोड़ रुपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल लगभग 6,400 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित हुआ था जो कि इस साल बढ़कर 7,938 करोड़ रुपए हो गया है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतों के सुझावों के तहत 100 वेंडरों को भी इस नई नीति के तहत कम किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब के अंतर्राज्जीय आवागमन को बेहतरीन नियंत्रण के लिए ट्रांसिट स्लिप को शुरू किया गया हैं तथा ट्रैक एवं ट्रेस सिस्टम के तहत हाई सिक्योरिटी होलोग्राम को भी लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नकली व अवैध शराब जिन कंपनियों की होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट राज्य में किया जाएगा। हरियाणा में सभी डिस्टलीरिज व बोटलिंग प्लांटों पर फलो मीटर तथा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। बोटलिंग के तहत क्यूआर कोड सिस्टम की सुविधा भी होगी जिसके तहत पारदर्शिता पर बल रहेगा।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में कई राज्यों से छोटा हैं, लेकिन जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमारा जीएसटी संग्रहण 16 प्रतिशत बढ़ा है जिसके तहत कुल जीएसटी संग्रहण 35,390 करोड़ रहा है जबकि पिछले वर्ष यह 30,507 करोड़ रुपए रहा था। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं इसलिए हमने जीएसटी संग्रहण का 40 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बताया कि इस वर्ष एसजीएसटी का कुल संग्रहण 15,115 करोड़ रुपए रहा है जोकि पिछले वर्ष 11,959 करोड़ रुपए रहा था। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे विभाग द्वारा 12 से 15 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया जो जीएसटी चोरी पर नकेल कसने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। इसके अलावा, हमने हरियाणा को मॉडयूल-1 से बदलकर मॉडयूल-2 में शिफट करने का काम किया और आंकडों में देरी के समय को भी कम करने का भी प्रयास किया गया। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि हरियाणा में 30 करोड़ रुपए की लागत से जीएसटी कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया जिसमें हाई स्पीट इंटरनेट, कम्यूटर, आर्टिफिशियल इंटलीजेंस पर बल देकर उसे अपग्रेड किया गया है।

एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को मंजूरी

मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई

हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में एक बिलियन अमरीकी डालर का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर हरियाणा को देश के अग्रणी एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है और रक्षा व्यय के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत खर्च किया है। इसलिए हरियाणा में एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण करने के लिए इस नीति की आवश्यकता महसूस की गई। यह नीति एयरोस्पेस व रक्षा उद्योग के लिए घरेलू परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में भी मदद करेगी।

नीति में ऑटो घटकों और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण के विभिन्न पहलुओं जैसे बुनियादी ढांचे में वृद्धि, आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, मानव पूंजी विकास, कनेक्टिविटी को मज़बूत करने आदि की भरपूर संभावना है।

इसके अतिरिक्त, नीति में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने तथा राज्य में आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग में औद्योगिक विकास की परिकल्पना की गई है।

इस नीति के माध्यम से, हरियाणा सरकार राज्य में मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम जैसे पाठ्यक्रम विकास, अनुसंधान एवं नवाचार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एयरोस्पेस एवं रक्षा विश्वविद्यालय और फ्लाइंग स्कूल की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति हरियाणा में एक विश्व स्तरीय एमआरओ बनाने की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। विमानन क्षेत्र में हो रहे विकास के मद्देनजर देश में परिचालित विमानों के लिए मेंटेनन्स, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। राज्य सरकार हरियाणा में मौजूदा हवाई अड्डों या नए स्थानों पर नई एमआरओ सुविधाओं की स्थापना के प्रस्तावों को सुविधाजनक और प्रोत्साहित करेगी।

यह नीति एमएसएमई क्षेत्र के विकास और इसके व्यवसाय के विकास पर विशेष जोर देती है। राज्य सरकार ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहल की हैं। राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास, बाजार संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, नियामक सरलीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट तथा वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय प्रोत्साहनः शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति - एफसीआई की 125 प्रतिशत की सीमा तक डी श्रेणी के ब्लॉकों में 10 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। सी श्रेणी के ब्लॉकों में 8 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। बी श्रेणी के ब्लॉकों में 7 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अनुसंधान एवं विकास सहायता : राज्य में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत इकाइयों को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक प्रदान की जाएगी।

ठेकेदार पंजीकरणः राज्य सरकार के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नियमों के अनुसार, अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर ठेकेदारों की आईडी सृजित करना अनिवार्य होगा। हालांकि ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना वैकल्पिक है, लेकिन ठेकेदार के लिए कुछ मूल जानकारी दर्ज़ करते हुए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाना आवश्यक है।

हरियाणा उद्यम संवर्धन : हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति में प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी नंबरदारों को मोबाइल-मेला लगाकर 9 हजार रुपए की कीमत के उनकी पसंद के मोबाइल सैट दिए जाएं।

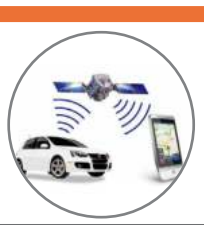

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य आगाज

विशेष प्रतिनिधि

पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 के चौथे सीजन का शानदार एवं भव्य आगाज हो गया। इस कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर (मस्कट), लोगो, जर्सी और थीम गीत लॉन्च किया गया।

खेलों के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ताऊ देवीलाल खेल परिसर, पंचकूला में हॉकी एस्ट्रोटर्फ, वॉलीबॉल इन्डोर हॉल व बास्केटबॉल इन्डोर हॉल का निर्माण करवाया गया है। सिंथैटिक एथलैटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन हॉल आदि का नवीनीकरण करवाया गया है। अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्डोर स्वीमिंग पूल का निर्माण भी किया गया है। अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीन संस्करणों का आयोजन किया गया है और हरियाणा में यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है और खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल हरियाणा में होने वाले इन खेलों में आ रहा है, जो गर्व की बात है।

हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भले ही छोटा प्रांत है, लेकिन ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के दल में 25 प्रतिशत यानी 30 खिलाड़ी हरियाणा से थे। हरियाणा ने सर्वाधिक पदक जीतने में मील का पत्थर स्थापित किया है।

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने ओलम्पिक व पैरालम्पिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की एडवांस राशि देने की व्यवस्था की है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए भी नई नीति लागू की गई है। अब पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और खेल श्रेणी का ग्रेड-सी प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

चार से 13 जून तक होगी प्रतियोगिता

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून, 2022 तक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में 25 तरह के खेल आयोजित होंगे, जिनमें पांच पारंपरिक खेल जैसे गतका, कलारीपयट्टु, थांग-ता, मलखंब और योगासन शामिल हैं। ये खेल पांच स्थानों पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 में 8,000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इन खेलों के गवाह बनेंगे।

हरियाणा की संस्कृति में रचे-बसे हैं खेलः सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेल हरियाणा की संस्कृति में रचे-बसे हैं। तीज-त्योहारों पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं से खेलों के प्रति यहां के जनमानस की रुचि बखूबी झलकती है। इसी खेल संस्कृति के चलते यहां खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा भले ही छोटा-सा प्रान्त हो परन्तु यहां खेल प्रतिभाओं की भरमार रही है। जरूरत केवल इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल-सुविधाएं और अवसर प्रदान करने की थी। हमने इस बात को समझा और खिलाड़ियों को अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का काम किया। इससे राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने की नीति पर काम कर रही है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं, खेल अकादमियों और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की गई है। बच्चों में खेल संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इससे राज्य के लगभग 25000 नवोदित खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। इन नर्सरियों में प्रशिक्षण लेने वाले 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह तथा 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा को स्पोर्टस हब बनाने की योजना है।

सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु 'हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018' बनाये हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। इसके अलावा, 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों के लिए क्लास वन से क्लास फोर तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है।

खिलाड़ियों को सबसे अधिक नकद इनाम

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि जितने भी खेल के टूर्नामेंट हुए हैं, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक सभी में हरियाणा की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि हम हमारी भूमिका बेहतरी से निभाएंगे ताकि हमारा देश दुनिया में परचम लहरा सके।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल व खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह गुरुग्राम में आयोजित 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021' चौथा संस्करण की प्रमोशनल सेरेमनी के दौरान खेलोइंडिया यूथ गेम्स-2021 का हरियाणा का मस्कट 'धाकड़' व यूथ गेम्स के मस्कट जया और विजय के साथ

खेल व खिलाड़ी को प्रोत्साहन

हरियाणा खिलाड़ियों की धरा है और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले अपन खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा नकद पुरस्कार व पद से सम्मानित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा प्राप्त पदकों में से लगभग एक-तिहाई पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। हरियाणा के पैरालम्पिक खिलाड़ियों ने भी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन किया है। राज्य में साहसिक खेलों के बढ़ावा देने के लिए नित नये प्रयास किये जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में खेल एवं युवा मामले क्षेत्रों के लिए 540.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि चालू वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 37.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

खिलाड़ियों का उपचार

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का लक्ष्य रखने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता करने तथा चोट लगने पर उनके उपचार के लिए, ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र (एस.टी.आर.सी.एस) की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर भविष्य में करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में ऐसे केंद्र खोले जा सकते हैं।

राज्य खेल संस्थान स्थापित

सरकार की राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.आई.एस) की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की योजना है, जहां स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन,स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी और खेल प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकते हैं। इस वर्ष एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है और सरकार ने पात्र खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि (पार्टिशिपेशन अवार्ड मनी) का एक-तिहाई जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि वे इन खेलों की तैयारी कर सकें।

खेल नर्सरियों में प्रशिक्षण

युवा खेल प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 1,100 खेल नर्सरियां खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से, 500 नर्सरियां सरकार द्वारा चलाई जाएंगी और 600 नर्सरियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी कोचिंग सेंटरों को आवंटित की जाएंगी। इन नर्सरियों से प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के इच्छुक लगभग 25,000 युवा लाभान्वित होंगे। खेल अकादमी योजना के तहत, सरकार की विभिन्न खेल श्रेणियों में दस डे-बोर्डिंग और आठ आवासीय अकादमियों को शुरू करने की योजना है, जहां सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खेल अवसंरचना के रख-रखाव, प्रबंधन और विकास के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक समिति गठित की जायेगी।

युवा उद्यमिता को बढ़ावा

हरियाणा साहसिक खेल अकादमी के तहत 'मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब' के माध्यम से सरकार साहसिक गतिविधियों में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। युवा उद्यमिता (यूथप्रिन्योरशिप) कार्यक्रम तीन प्रकार के मानवीय, वैचारिक और तकनीकी कौशल पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत पंचकूला के मोरनी में युवा उद्यमियों का दस दिवसीय बूट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 40 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश-भर में शुरू किया जाएगा और आगामी वर्ष में 1,000 युवाओं को साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी आजीविका में मदद मिलेगी।

-संगीता शर्मा

प्रदेश के सभी शहरों को हरा भरा करने के लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त हार्टिकल्चर विंग तैयार किया जाएगा। इस विंग को अपनी नर्सरी और अन्य संसाधन भी उपलब्ध होंगे।

हरियाणा सरकार ने बहु मंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सुरक्षा एजेंसी इमारत के निर्माण के दौरान तीन से चार बार सुरक्षा मानकों का ऑडिट करवाएगी।

तख़्ती और स्कूल बै

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज किया है। इस क्रांति के अग्रज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से 'ई-अधिगम' योजना का शुभारंभ करते हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पांच लाख टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इसी दिन प्रदेश के 119 जगहों पर टैबलेट वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद भी किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के छात्रों को पहले पुस्तकों को बैग में भरकर लाना पड़ता था लेकिन आज से इस टैब में ही उनकी किताबें आएंगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में तकनीक को अपनाकर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है जबकि हम 2025 तक इसे लागू करने को लेकर संकल्पित हैं।

प्रदेशभर के 10वीं से 12वीं तक के 3 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जा रहे हैं और जल्द अन्य 2 लाख टेबलेट भी वितरित कर दिए जाएंगे। यह टेबलेट विद्यार्थियों के साथ-साथ 33 हजार शिक्षकों को भी दिए जा रहे हैं ताकि वे विद्यार्थियों को अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा सके। नौंवी कक्षा के विद्यार्थियों को भी टैबलेट दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ तख्ती पर लिखा करते थे लेकिन आज उस तख्ती की जगह टैबलेट ने ले ली है। अब बच्चे इसपर अभ्यास करेंगे। ई-अधिगम योजना शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में और भी कई सुधार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण शिक्षा क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा और स्कूल बंद करने पड़े, लेकिन अब टैबलेट नया क्लासरूम बन गया है। और ई बुक्स के माध्यम से तो यह फुल फ्लेज्ड क्लास रूम ही बन गया है।

यूनिवर्सिटी में केजी से पीजी तक की पढ़ाई

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ई-अधिगम एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में केजी (किंडर गार्टन) से पीजी (स्नातकोतर तक) कक्षाएं शुरू की जा रही है। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा केजी से पीजी तक कक्षाएं शुरू कर दी गई है तथा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इन कक्षाओं को शुरू किया जाएगा।

हिन्दी में भी होगा मेडिकल, इंजीनियरिंग व लॉ का पाठ्यक्रम

प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं लॉ कॉलेज में हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम तय किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए है तथा सरकार द्वारा 500 नए ऐसे स्कूल खोले गए है।

प्रदेश में 14 हजार राजकीय स्कूल है, इनमें से कुछ स्कूलों के भवन पुराने है। सरकार द्वारा आयु सीमा पूर्ण कर चुके स्कूल भवनों की जांच करवाकर इनके स्थान पर नए भवन बनाने का आह्वान किया है।

झारखंड में हरियाणा को आवंटित कोल ब्लॉक को विकसित करने तथा यमुनानगर में 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का एक संयत्र स्थापित करने में केंद्र द्वारा हरियाणा को पूर्ण सहयोग किया जाएगा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके और उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति हो सके।

ग की जगह टैबलेट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से किया 'ई-अधिगम' योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज आईटी का युग है। बहुत सारे छोटे-छोटे देशों की अर्थव्यवस्था आईटी पर आधारित है। इजराइल, ट्यूनिशिया और फिनलैंड जैसे देशों ने आईटी स्टार्टअप के माध्यम से काम किया है। छोटे-छोटे देश आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति को महत्व दे रही है। इसके तहत छोटे से छोटे लेवल पर विद्यार्थियों को आईटी की शिक्षा देनी शुरू करेंगे। नई शिक्षा नीति को जहां देशभर में 2030 तक लागू किया जाएगा वहीं हरियाणा ने इसे 2025 तक लागू करने का लक्ष्य लिया है।

हरियाणा अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। इस बार के बजट में अकेले 20 हजार करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके लिए बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। स्कूलों की दशा में और सुधार करने के लिए अनेक पहल की गई हैं। इनके अलावा सरकार दो टास्क फोर्स बनाने जा रही है। एक

शिक्षा क्षेत्र में होगा आमूल चूल परिवर्तन

टास्क फोर्स स्कूलों का इंफास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, चारदीवारी, सुंदरता, स्वच्छता, रास्ते, पानी और शौचालय सहित अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर काम करेगी तो दूसरी टास्क फोर्स स्कूलों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल के अंदर बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।

आईटी के क्षेत्र से बच्चों को किया जाएगा दक्ष

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आईटी के क्षेत्र में कौशल हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की आईटी स्किल को निखारने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। बच्चों को 3-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, एआई, ब्लॉक चेन सहित अन्य तकनीकों का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईटी ट्रेंड युवक कहीं भी देश दुनिया में काम कर सकते हैं, उनके लिए रोजगार के रास्ते खुल जाते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में हरियाणा के युवा देश और दुनिया में पहली पसंद बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अलग से फॉरन कॉपरेशन विभाग बनाया गया है जिसके जरिए दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क कर वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मैनपावर भेज सकते हैं।

छात्रों के लिए विषयवार ओलंपियाड की शुरुआत

फिजिक्स और गणित के विद्यार्थियों में अच्छी प्रतियोगिता हो, इसके लिए छात्रों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। इसमें अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को नासा और इसरो जैसी संस्थाओं में भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर ओलंपियाड होंगे, इनमें शामिल विद्यार्थियों को छात्रवृति और पुरस्कार भी दिया जाएगा।

एनडीए लेवल की तैयारी करवाई जाएगी

भारतीय सेना में 10 फीसद हरियाणा के युवा हैं। लेकिन सेना में हरियाणा के अफसरों की संख्या काफी कम है। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को एनडीए लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। एनडीए की कोचिंग के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

शिक्षा के साथ संस्कार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राचीन समय में अध्यापक व विद्यार्थियों में स्नेह का रिश्ता होता था तथा घर परिवार जैसा वातावरण होता था। अध्यापक विद्यार्थियों का पढ़ाई के मामलें में पूर्ण मार्गदर्शन करते थे तथा उन्हें घर के सदस्यों की तरह स्नेह करते हुए अच्छे संस्कार देते थे। वर्तमान समय में इसमें काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज भी पहले की तरह अध्यापक विद्यार्थी में रिश्ता होना चाहिए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल बनियानी गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में बच्चों के साथ अपना 69वां जन्मदिन मनाने के दौरान विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गांव में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मनोहर लाल बनकर आये है। बचपन में उनकी दादी घर में उन्हें मन्नु के नाम से पुकारती थी। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में बनाई गई मनोहर वाटिका में पौधारोपण किया तथा आंगनवाड़ी के बच्चों सहित इस वाटिका में 68 पौधे रोपे गये।

आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से बेटियों में बढ़ा आत्मविश्वास

आत्मरक्षा का प्रशिक्षण संकट की स्थिति में बेटियों के बचाव में सहायक व उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इसके साथ ही बेटियां शारीरिक और मानसिक रूप से सबल भी बनती है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल पंचकूला में शिक्षा विभाग एवं हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद द्वारा आयोजित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। हरियाणा के विद्यालयों में यह कार्यक्रम काफी सफलता के साथ चलाया जा रहा है जिसके आगे भी अच्छे परिणाम आएगे। पिछले शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के लगभग 3 हजार विद्यालयों जिसमें मौलिक विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसके तहत लगभग 3 हजार विद्यालयों की लगभग 1,23,302 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया।

'शिक्षा सारथी' पत्रिका का विमोचनः श्री कंवर पाल ने 73 छात्राओं कराटे बेल्ट देकर सम्मानित किया और विद्यालय शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका 'शिक्षा सारथी' के अप्रैल अंक का विमोचन भी किया, जो छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर ही आधारित है।

10 मेधावी विद्यार्थियों को दिए स्मार्ट फोनः शिक्षा मंत्री ने कहा कि 137 संस्कृति आदर्श विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रोग्रेमिंग (कोडिंग) का प्रशिक्षण नवगुरुकुल फाउंडेशन गुरुग्राम के द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से दिया। उन्होंने इस अवसर पर दस मेधावी विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन व इस प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले पांच अध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण से छात्राओं में बढ़ा विश्वास

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए पूर्णत संजीदा है। सरकार द्वारा सेल्फ डिफेंस हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत बेटियों को मार्शल आर्ट और जूडो की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे किक या एक पंच ही किसी हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त है। लड़कियों को हर दिन काम में आने वाली चीज़ों जैसे-चाबी की चेन, दुपट्टा, स्ट्रोल, मफलर, बैग, पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि का उपयोग अवसर के अनुरूप हथियारों के रूप में करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण से बेटियों का न केवल आत्मबल जागृत होगा, बल्कि उनका चहुमुंखी विकास भी होगा। प्रशिक्षण ले रही हर छात्रा को अपने मोबाइल फोन में 'दुर्गा शक्ति ऐप' को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा उन्हें टोल फ्री नंबर- 112 की जानकारी भी दी गई।

आत्मरक्षा के गुर

- नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, ध्यान करें, पौष्टिक आहार लें।
- आत्मविश्वास विकसित करें।
- चारों तरफ़ ध्यान देकर चलें आस-पास हो रहे, घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखें।
- जहां जा रहे हैं उस रास्ते व साधनों की पूरी जानकारी रखें। समय का ध्यान रखकर चलें।
- अगर कोई व्यक्ति बार-बार पीछा कर रहा है, गलत हरकत करता है तो परिजनों को जानकारी दें।
- बाइक या गाड़ी से कोई छेड़खानी करके जा रहा है तो गाड़ी नंबर नोट कर पुलिस को सूचना दें।
- अनजान व्यक्ति को फेसबुक, व्हाट्सएप फ्रेंड न बनाएं।
- अजनबियों को अपना मोबाइल नंबर न दें।

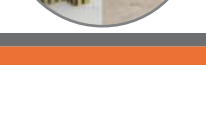

हरियाणा का पीपीपी मोड पर फरीदाबाद में बनने वाला पहला हाईटेक बस टर्मिनल सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। टर्मिनल में बस अड्डा के अलावा कमर्शियल हब भी होगा।

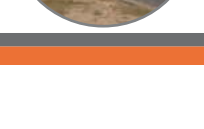

हिसार में बनाए जा रहे एयरपोर्ट पर 10,000 फुट रनवे का कार्य जुलाई माह में पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा, चरण-2 के अंतर्गत ऑपरेशनल बिल्डिंग, एमआरओ एवं कार्गो ऑपरेशन का कार्य भी तेज़ गति से हो रहा है।

एक लाख एकड़ सेमग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य

हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजैक्ट (एचओपीपी) किसानों की सेमग्रस्त भूमि के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके तहत प्रदेश की एक लाख एकड़ सेमग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि एचओपीपी के तहत सब सरफेस ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से सेमग्रस्त भूमि का उपचार किया जाता है।

रोहतक के गांव काहनी में इस परियोजना के सौ फ़ीसद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जहां 400 एकड़ कृषि भूमि में उपरोक्त तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक के प्रयोग से पहले यहां उपरोक्त क्षेत्र में गर्मी के दिनों में भी सेम की वजह से खेतों में एक से डेढ़ फुट पानी खड़ा रहता था और नमक भी दिखाई देता है, जिसके चलते किसान किसी भी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस भूमि में सीजन के अनुसार फसलों का भरपूर उत्पादन हो रहा है, जो कि बेहद खुशी की बात है। कथूरा में भी इसी प्रकार से एचओपीपी के माध्यम से सेमग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाये गये हैं।

प्रदेश सरकार सेमग्रस्त व बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से इस परियोजना को प्रदेश भर में क्रियान्वित किया गया है। अब तक इस परियोजना के तहत प्रदेश का 28250 एकड़ क्षेत्र कवर किया जा चुका है।

ऐसे काम करती है तकनीक

सब सरफेस ड्रेनेज तकनीक के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें 2 से 3 मीटर की गहराई में पाइप दबाए जाते हैं। इन पाइपों में छेद होता है। पाइपों के माध्यम से पानी को एक कुएं रूपी गड्ढे में इकट्ठा करके उसकी निकासी की जाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत खेतों से पानी निकासी के तमाम विकल्प भी अपनाए जा रहे हैं। इस परियोजना के साथ मत्स्य पालन को भी जोड़ा जा रहा है।

बराला ने प्रदेश के किसानों को आह्वान किया कि अगर उनके खेतों में भी सेम की समस्या है तो वे उपरोक्त क्षेत्रों में आकर इस कार्य को अवश्य देखें। अपनी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाएं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अपनाने के लिए प्रदेश के करीब 18 हजार किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है।

किसानों को अनुदान

उन्होंने बताया कि इस परियोजना को अपनाने पर एक एकड़ क्षेत्र में 45 हजार का खर्च आता है, जिसमें से किसान को मात्र 10 प्रतिशत की राशि ही देनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 12 जिलों में सेम की समस्या को चिन्हित किया गया है, जहां इस परियोजना का विशेष लाभ किसानों को मिलेगा।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

हरी खाद
मिट्टी के लिए वरदान

दलहनी फसलें अपनी जड़ ग्रंथियों में उपस्थित सहजीवी जीवाणु के द्वारा वातावरण से नाइट्रोजन का दोहन कर मिट्टी में स्थिर करती है। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलें अपने विशेष गुणों जैसे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने, मृदा क्षरण से बचाने, मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाने, पोषकीय चारा व दालों द्वारा प्रोटीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराने में मुख्यः भूमिका निभाती है।

हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलें जैसे कीसनई (सनहेम्प), ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि फसलों को उपयोग में लाया जाता है। ये फसलें शीघ्र वृद्धि वाली तथा कम समय में तैयार हो जाती है और इनकी पत्तियां ज़्यादा संख्या में बड़ी और वज़नदार होती है जिससे कम समय में अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इन फसलों की उर्वरक तथा पानी की आवश्यकता प्रायः और फसलों के मुकाबले कम होती है।

ऐसे स्थानों पर जहां जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहा सनई का उपयोग किया जाता है, ढैंचा को सूखे की दशा वाले स्थानों में तथा समस्याग्रस्त भूमि में जैसे क्षारीय दशा में उपयोग में लाया जा सकता है। ग्वार को कम वर्षा वाले स्थानों में रेतीली, कम उपजाऊ भूमि में लगाया जाता है। लोबिया को अच्छे जल निकास वाली क्षारीय मृदा में तथा मूंग, उड़द को खरीफ या ग्रीष्म काल में ऐसे भूमि में ले जहां जल भराव न होता हो। इससे इनकी फलियों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है तथा शेष पौधा हरी खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

हरी खाद देने की विधियां

हरी खाद की स्थानिक विधि (इन सीटू विधि): इस विधि में हरी खाद की फसल को उसी खेत में उगाया जाता है जिसमें हरी खाद का प्रयोग करना होता है। यह विधि समुचित वर्षा या सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस विधि में फूल आने के पूर्व वानस्पतिक वृद्धि काल (40-50 दिन) में फसल को मिट्टी में पलट दिया जाता है। मिश्रित रूप से बोई गयी हरी खाद की फसल को उपयुक्त समय पर जुताई द्वारा खेत में दबा दिया जाता है।

हरी पत्तियों की हरी खाद: इस विधि में हरी पत्तियों एवं कोमल शाखाओं को तोड़कर खेत में फैलाकर जुताई द्वारा मृदा में दबाया जाता है। जो मिट्टी मे थोड़ी नमी होने पर भी सड़ जाती है। यह विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होंती है।

जब फसल की बढ़वार अच्छी हो गई हो और फूल आने से पहले इसे हल या डिस्क हैरो से खेत में पलट कर पाटा चला देना चाहिए। जुताई उसी दिशा में करनी चाहिए जिसमें पौधों कों गिराया गया हो। इसके बाद खेत में आठ-दस दिन तक चार-छह से.मी. पानी भरा रहना चाहिए जिससे पौधों के अपघटन में सुविधा होती है। यदि पौधों को दबाते समय खेत में पानी की कमी हो या देर से जुताई की जाती है तो पौधों के अपघटन में अधिक समय लगता है।

हरी खाद के लाभ

- भूमि के जीवांश कार्बन में वृद्धि होती है तथा मिट्टी के अंदर में जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है।
- भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाता है जिससे रसायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है।
- भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्ता बढ़ जाती है जिसकी वज़ह से पैदावार में बढ़ोतरी होती है।
- हरी फसलों के उगाने से भूमि की ऊपरी परत वर्षा की बूंदों के प्रत्यक्ष प्रहार से बच जाती है जिसकी वज़ह से ना केवल भूमि अपरदन में कमी आती है बल्कि भूमि की पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है।
- भूमि की रचना एवं संरचना में वृद्धि होती है तथा हल्की मिट्टी में जल रिसाव भी कम हो जाता है जिसकी वज़ह से भूमि में नमी लंबे समय तक बनी रहती है।
- हरी खाद वाली फसल के घने एवं शीघ्र बढ़ने के कारण खरपतवार पनपते नहीं है।

सुनीता फोगाट, रोहतास कुमार, रचना (मृदा विज्ञान विभाग) और सिंधु श्योराण (कीट विज्ञान विभाग), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

मौसम की बेरुखी से नींबू की कीमत में उछाल

संगीता शर्मा

गर्मियों के मौसम में नींबू पानी व अन्य पेय पदार्थ न केवल हमको तरोताज़ा महसूस करवाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह फल गुणकारी होता है। लेकिन इस वर्ष नींबू की बढ़ती कीमत के कारण यह आम वर्ग की पहुंच से दूर हो गया। कृषि वैज्ञानिकों व किसानों का कहना है कि इस वर्ष अचानक बदलते मौसम कभी बारिश, ओले व बढ़ते तापमान के कारण नींबू की फसल अच्छी नहीं हो पायी। ज़्यादा बारिश की वज़ह से नींबू के पेड़ में फूल ही नहीं आए, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। दूसरी ओर, इस वर्ष फरवरी माह में नींबू की फसल अच्छी हुई थी, जिसके चलते किसानों को 25 रुपए प्रति किलो दाम ही मिले। जबकि अप्रैल माह में नींबू 300-400 रुपए प्रति किलो व मई में 200-250 रुपए प्रति किलो नींबू बिक रहा है। इसके चलते अब किसानों ने फरवरी माह में कोल्ड स्टोर में नींबू रखने का मन बना लिया है, ताकि गर्मियों के मौसम ने नींबू की फसल से ख़ासा मुनाफ़ा कमा सकें।

रेवाड़ी के मशीत गांव के एमबीए पासआउट अजय यादव सात एकड़ ज़मीन में नींबू का बाग और 40 एकड़ ज़मीन में मौसमी सब्ज़ियों की खेती करते हैं। इसमें तोरी, बैंगनी, भिंडी, ककड़ी व तरबूज़ शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि 2,500 'बाला जी' किस्म के पौधे रोपित किए हैं और यह कागजी नींबू है। इससे मंडी में बहुत पसंद किया जाता है और इसके खरीददार अधिक है। इसका आकार सामान्य और रसीला होता है। उन्होंने बताया कि सात एकड़ ज़मीन पर नींबू की खेती में पौधे की कीमत, सूक्ष्म सिंचाई, फेसिंग, लेबर और अन्य सभी खर्चे मिलाकर करीब नौ लाख रुपए खर्चा आया है। उन्होंने बताया कि इस बार नींबू की फसल को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण बाज़ार में इसके दाम बहुत महंगे हैं। वह कहते है कि अगले वर्ष नींबू की फसल से मुनाफ़ा कमाने की आस लगा रहे हैं।

नींबू का आकार छोटा व पैदावार कम

निमोठ के कृष्ण आधा एकड़ ज़मीन में नींबू की खेती कर रहे हैं। फरवरी माह में दो क्विंटल नींबू की पैदावार हुई और मंडी में कीमत 25 रुपए किलो मिली। जिसके कारण उचित लाभ नहीं कमा सकें। कृष्ण ने बताया कि इस बार फूल आया लेकिन फल के समय तापमान अधिक होने से फल का आकार छोटा और पैदावार बहुत कम हुई। उन्होंने बताया कि पैदावार कम होने से वह नींबू को मंडी तक बिक्री के लिए नहीं ले जा सकें। डहिना हर्बस किसान उत्पादक संगठन के सदस्य कृष्ण कहते है कि अगली बार वह नींबू की फ़सल से अधिक लाभ कमाएंगे। उनके समूह का कोल्ड स्टोर तैयार हो गया है। इसलिए वह फरवरी माह में नींबू की पैदावार को कोल्ड स्टोर में रखेंगे ताकि गर्मी के मौसम में अच्छे दाम लेकर फ़ायदा उठा सकें। उनका कहना है कि नींबू की खेती करते समय कलम की अपेक्षा बीज से नींबू का पेड़ अच्छा तैयार होता है।

जून में आएगा हरियाणा का नींबू

कृषि महाविद्यालय, बावल, रेवाड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार का कहना है कि मौसम की मार के कारण इस वर्ष नींबू फसल की पैदावार कम हुई है। इस समय महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना से नींबू की आवक आ रही है और जून माह में हरियाणा/उत्तर भारत का नींबू आना शुरू हो जाएगा। उस समय नींबू की कीमत में कमी आएगी।

किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना किसानों व मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का लाभ उन्हीं किसान व मजदूरों को मिलता है जो खेत या अन्य स्थानों पर कार्य करते वक्त दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं।

खेत में जैसे कृषि यंत्र, आग लगने, जहरीले जीव द्वारा काटने, वाहन दुर्घटना, कीटनाशक दवा का छिड़काव करते आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसान या मजदूर को हानि होती है।

इसके मुआवजे के लिए मार्केट कमेटी कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है। दुर्घटना के कारणों का ब्यौरा देना होता है। सरंपच, दो पंच या नंबरदार के हस्ताक्षर के बाद आवेदन पूरा माना जाता है। स्वास्थ्य केंद्र जहां चिकित्सा हुई हो, का नाम व पूरे पत्ते के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होता है।

मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए, रीढ की हड्डी टूटने या अन्यथा किसी कारण से स्थाई अपंगता होने पर अढ़ाई लाख रुपए तथा अपंगता के आधार पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए मार्केट कमेटी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य मार्केट बोर्ड, पंचकूला के मुख्य मार्केटिंग विकास अधिकारी सुधीर के अनुसार यह योजना किसानों मजदूरों के लिए कारगर साबित हो रही है। मार्च 2021 तक 6882 केस रजिस्टर किये गये थे। इस योजना के तहत पीड़ित व्यक्ति का उतराधिकारी आवेदन कर इसका लाभ ले सकता है।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस बार सीसीटीवी कैमरों की देख-रेख में किया जाएगा। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

प्रदेशभर में सभी साइनेज और सड़कों के किनारे लगे मील के पत्थरों का नवीनीकरण करने के साथ-साथ इन पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतीक चिह्न लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आजादी के अमृत महोत्सव की सुनहरी यादें रहें।

अमृत सरोवर मिशन

पानी की एक-एक बूंद के सदुपयोग का संकल्प

मनोज प्रभाकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर मिशन का हरियाणा में आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सोनीपत के गांव नाहरा में गंगेश्वर सरोवर पर नारियल तोड़कर योजना का शुभारंभ किया। इसी दिन से राज्य के अन्य 111 स्थानों पर इस योजना की शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'जल ही जीवन है' के मूल मंत्र को समझा है और देशभर के तालाबों को बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने देशभर के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को साफ़ करने या उनका जीर्णोद्धार करने की योजना पर काम करने के लिए कहा है। यह योजना उसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग पारस्परिक सहयोग से तालाब खोदते थे। लेकिन काफ़ी समय से लोगों ने तालाबों की साफ़-सफ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण ये प्रदूषित हो गए। समय के साथ-साथ इन तालाबों में अपशिष्ट मिलने लगे। तालाबों का पानी ओवरफ्लो होने लगा लेकिन आज से हमने इसको ठीक करने का बीड़ा उठाया है।

सरकारी भवन में बनेगा रिचार्जिंग वेल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की एक-एक बूंद को बचाकर उसे प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत प्रदेशभर के सभी सरकारी भवनों में रिचार्जिंग वेल लगाए जाएंगे ताकि बरसाती पानी का संरक्षण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बरसाती पानी को संरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 750 रिचार्जिंग बोरवेल लगाए गए थे। इस वर्ष इनकी 5 हजार करने का लक्ष्य तय किया गया है।

रिसाइक्लिंग किए गए पानी का उपयोग

योजना के मुताबिक उद्योगों, सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी को एसटीपी के माध्यम से रिसाइक्लिंग करके उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस पानी को पुनः उद्योगों, निर्माण कार्यों, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बागवानी और खेती के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पानी में खाद के अव्यव होते हैं, जो सब्ज़ी, फल, फूल व खेती के लिए बेहद लाभदायक है। इस रिसाइक्लिंग पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए एचएसवीपी को डबल लाइन बिछाने के लिए भी कहा गया है। इसे घरों में गाड़ी धोने, शौचालय और बागवानी आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऐसे तो जमीन का पानी खत्म हो जाएगा

शुद्ध पानी की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 82 लाख एकड़ कृषि योग्य ज़मीन है। इसमें से सीधे सिंचाई 40 लाख एकड़ ज़मीन पर की जाती है, बाकि ज़मीन पर हम स्वच्छ पानी न होने की वज़ह से सीधे सिंचाई नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें माइक्रो इरिगेशन प्रणाली को अपनाना चाहिए। सरकार द्वारा इसके लिए 85 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, महज 15 प्रतिशत पैसा ही किसानों को लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल से सिंचाई करने की वज़ह से हर साल एक मीटर जलस्तर नीचे जा रहा है। किसान की भाषा में समझें तो उसे हर साल एक मीटर का पाइप बोरवेल में डालना पड़ता है। ऐसे यदि 10-20 साल हम करते रहे तो ज़मीन में पानी खत्म हो जाएगा। यह वैसी ही स्थिति होगी, जैसी हमारे शरीर से रक्त खत्म होने पर हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जमीन की ऊपजाऊ शक्ति खत्म होने के साथ-साथ भावी पीढ़ी को बंज़र भूमि ही मिलेगी। धान जैसी फसलों में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, इन फसलों की खेती न करें। इसके लिए सरकार प्रत्येक वर्ष सात हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत किसानों ने एक लाख एकड़ पर धान की बिजाई कम की है।

भू-जल रिचार्जिंग का कार्य

हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पीडीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में सरकारी ज़मीन पर स्थित सभी तालाबों का डाटा एकत्रित किया गया है, जिनकी 27 अप्रैल 2022 तक कुल संख्या 18,827 (ग्रामीण 17,971 और शहरी 856) है। इन तालाबों में बहने वाले अपशिष्ट जल को कंस्ट्रक्टिड वेटलैंड तकनीक के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है, ताकि इन जीर्णोद्धार किए गए तालाबों के जल का उपयोग मछली पालन, पशुओं के उपयोग के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई के लिए किया जा सके। इसके अतिरिक्त भू-जल रिचार्जिंग का कार्य भी किया जा रहा है।

गंदे पानी का उपचार

वर्ष 2019-20 में लिए गए पहले 18 मॉडल तालाबों में से नौ तालाब पूरे हो चुके हैं और शेष नौ तालाब 31 दिसंबर, 2022 तक पूरे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त गोहाना, सोनीपत में ट्रीब्यूट्री ड्रेन नंबर- 4 के गंदे पानी के उपचार का कार्य भी कंस्ट्रक्टिड वेटलैंड तकनीक द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार प्राधिकरण ने अतिप्रवाहित तालाबों सहित सभी प्रदूषित तालाबों के जीर्णोद्धार व पुनरुद्धार हेतु वित्त वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लिए क्रमशः द्वितीय व तृतीय चरण की कार्य योजना तैयार की है। द्वितीय चरण के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 736 गांवों के कुल 1,803 प्रदूषित तालाबों में से 694 गांवों के 1,609 तालाबों के आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्रॉइंग्स पहले ही जारी की जा चुकी हैं और शेष 30 अगस्त, 2022 तक जारी किए जाएंगे। इनमें से 149 तालाबों के कार्यों का आवंटन किया जा चुका है और 114 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है।

तालाबों का जीर्णोद्धार व पुर्नरुद्धार

तृतीय चरण के तहत वित्तय वर्ष 2022-23 में 1,044 गांवों के 2,558 प्रदूषित तालाबों के लिए कार्य योजना जारी है और 31 अक्तूबर, 2022 तक सभी आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स भी जारी कर दी जाएंगी। जल्द ही 105 तालाबों पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इन कार्य योजनाओं में 5,000 -10,000 की आबादी वाले कुल 562 गांवों में से 409 गांव और 10,000 से अधिक आबादी वाले 109 गांवों को शामिल भी किया गया है और शेष गांवों को चौथे चरण में लिया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से सरकारी भूमि पर स्थित सभी जल निकायों की जियो-मैपिंग और जियो टैगिंग करवाई जा रही है, जिसके 30 जून, 2022 तक पूरा होने की संभावना है। प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष 2,500 तालाबों का जीर्णोद्धार व पुर्नरुद्धार किया जाएगा और इसके लिए आगामी वर्षों में प्राधिकरण ने प्रदूषित व अतिप्रवाहित तालाबों सहित शेष सभी तालाबों का पुनर्निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हरियाणा सरकार ने 12 गांवों के 325 किसानों को लगभग पांच करोड़ की राशि के कृषि व पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड प्रदान किए हैं।

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में 10 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा।

बाबू बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक धरा- रेवाड़ी

रेवाड़ी प्राचीनकाल से अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पहचान के लिए विख्यात रहा है। इतना ही नहीं यह क्षेत्र पत्रकारिता के मसीहा तथा हिंदी गद्य के साहित्यकार स्व.बाबू बालमुकुंद गुप्त की अनमोल स्मृतियों को अपने आंचल में सहेजे है।

अहीरवाल की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी का संबंध महाभारतकाल से रहा है। मान्यता के मुताबिक उन दिनों यहां राजा रेवत राज करते थे। राजा रेवत की बेटी का नाम रेवती था,जिसे प्यार से रेवा कहा जाता था। रेवा का विवाह योगेश्वर श्रीकृष्ण के दाऊ बलराम से हुआ था। यह क्षेत्र रेवा को कन्यादान स्वरूप दान में दिया गया था। इसी के चलते इसे रेवा वाड़ी कहा जाने लगा,जो बाद में रेवाड़ी हुआ विवाह में पधारे श्रीकृष्ण को जहां ठहराया गया था, उस मोहल्ले को आज भी बलभद्र सहाय कहा जाता है, जो रेवाड़ी के वर्तमान प्रसिद्ध नाईवाली चौक के पास स्थित है। इसी प्रकार बारात में पधारे पांच पांडवों के ठहराव क्षेत्र के नाम से आज भी पांचेवाला मोहल्ला है। अहीरवाल की लोकगाथाओं तथा लोकगीतों में आज भी इन ऐतिहासिक प्रसंगों के उल्लेख मिलते हैं।

साहित्य और रेवाड़ी का नाम जुबान पर आते ही ज़हन में अनायास उभरकर छा जाते हैं हिंदी पत्रकारिता के मसीहा, हिंदी गद्य के जनक, राष्ट्रीयता के अग्रदूत स्व. बाबू बालमुकुंद गुप्त (18 65-1907), जिनकी अनमोल स्मृतियां आज भी उनकी जन्मस्थली जिले के गांव गुड़ियानी, उनकी ननिहाल ज़िले के गांव सीहा तथा उनकी ससुराल रेवाड़ी नगर अपने आंचल में सहेजे हैं। बहुआयामी

व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी राष्ट्रभक्त कलमकार गुप्त जी को भारतेंदु युग के सेनापति के रूप में ससम्मान याद किया जाता है। इतना ही नहीं हिंदी साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके निर्णायक अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन्हें आज भी कुशल संपादक, निर्भीक पत्रकार, ओजस्वी कवि, चिंतनशील निबंधकार, तटस्थ समीक्षक, सतर्क समालोचक, हिंदी उन्नायक, नवजागरण के पुरोधा, भावपूर्ण अनुवादक तथा देशभक्त कलमकार के रूप में अगाध श्रद्धा से याद किया जाता है। भारतेंदु तथा द्विवेदी युग के सेतु के रूप में लब्धप्रतिष्ठा छह भाषाओं में साधिकार कलम चलाने वाले गुप्तजी ने एक ओर जहां उर्दू अखबारों अवध-पंच, ज़माना, अख़बारे-चुनार,कोहेनूर, मथुरा अखबार, विक्टोरिया गजट, भारत प्रताप, गुलदस्ता में लेखन के अलावा अखबारे-चुनार एवं कोहेनूर में सफल संपादन भी किया, वहीं उन्होंने हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदोस्थान, हिंदी बंगवासी तथा भारतमित्र के संपादक के तौर पर नए आयाम रचे।

गुप्तजी ने अंग्रेजी काल में तानाशाही के खिलाफ अपनी लेखनी से आग उगलते हुए आजादी की अनूठी अलख जगाई थी जिसे शिवशंभू के लिखे चर्चित निबंधों व स्तंभों से समझा जा सकता है। क्रांतिकारी कलमकार बाबू बालमुकुंद गुप्त को अहीरवाल की वीर प्रसूता धरा से देशभक्ति, राष्ट्रीयता और राष्ट्रप्रेम के जो संस्कार मिले थे, उन्हीं के चलते वे राष्ट्रीयता के संवाहक व अग्रदूत कहलाए।

सत्यवीर नाहडिया

छाज, छलनी और पीसणा

बदलते परिवेश में हरियाणा प्रदेश का गांव-देहात भी अछूता नहीं है। खेत-खलियानों तथा घर-गृहस्थी के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली अनेक वस्तुओं का स्थान अब लगभग मशीनों ने ले लिया है। परंपरागत वस्तुएं तथा तौर-तरीके मानो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। या यूं कहिए कि लुप्त होने के कगार पर हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में हरियाणा की महिलाओं को महारत हासिल है। उन्हीं के पक्ष का एक कार्य जो प्रायः लुप्त होता जा रहा है वह है-छाज, छालणी से पीसणा करना।

छाज तै बोलै...छालणी भी के बोलै जिसमैं हजार छेद, कसाई का पीसणा काटड़ा खा लै और वहीं बहू का पीसणा अर वहीं ससुर की खाट....आदि हरियाणवीं कहावतें हम अक्सर सुनते व कहते रहे हैं। पुरानी पीढ़ी तो 'पीसणा' का मतलब समझती है, किंतु नई पीढ़ी पीसना और पीसणा का अंतर शायद ही जानती हो।

वस्तुतः आधुनिक युग में अनाज को सुरक्षित संग्रह के लिए उपयोग में ली जा रही स्टील या इस्पात की चद्दर से बनी टंकी से निकाल कर 'धान और छालणी' के द्वारा उसमें से डूंडला, भुरली, चित्ती, कब्बे, औगणें, कंकर, रोड़ी, धूल मिट्टी, गर्द आदि छान-फटक कर अलग करने के बाद जो साफ-सुथरा अनाज बचता है वह 'पीसणा' कहलाता है। दूसरे शब्दों में साफ-सफाई के बाद पिसने के लिए तैयार अनाज ही 'पीसणा' कहलाता है।

बदलते युग में आजकल ऐसी भी आटा चक्कियां आ गईं जो पीसने से पहले स्वयं ही 'पीसणा' करके आटा बना देती हैं। यद्यपि मानवीय हाथों से अर्थात सास-बहू के हाथों से किए पीसणे की कोई होड़ नहीं हो सकती तथापि नई-पीढ़ी की बहुएं छाज, छलणी और पीसणा के चक्कर से बचना ही चाहती हैं।

- राम निवास सुरेहली, रेवाड़ी

सुण छबीले बोल रसीले

हंसते और हंसाते रहो

छबीले, बेरा ना किसा टैम आग्या, जिसनै भी देखै मुंह लटकाए हांडै सै, किसे के मुंह पै हंसी कोन्या। टेंशन ए टेंशन दिखाई दे सै। टोक ले तों बी खास रिएक्शन कोन्या। काम की कह दें तो न्यू कहैंगे, टैम कोन्या।

-भाई रसीले, सब आपणी-आपणी समस्याओं में बिज़ी सैं। और फिर इस महंगाई के जमाने में हांसणा कोए आसान काम कोन्या।

-मेरे यार, यो महंगाई तो कदे तैं देखते आ रे सैं। महंगाई कदे कम होई सै ? बढ़ण की चीज तो बढ़ैगी। फेर जो काम होणाए सै तो उसका बुरा के मानणा। ठाली क्यूं बैठो, काम करो, आमदनी बढ़ाओ। ना भी बढ़ै तो क्या हांसणा ए छोड़ दे? आमदनी आज नहीं तो कल होज्यागी पर यो खूबसूरत देही फेर थोड़ा मिलैगी। इसमें डेंट पड़ग्या तो पड़े जावैगा, वो फेर मिटै कोन्या।

-हां रसीले, कई लोगां नै देखै सैं, शक्ल नै इसी बणाए राखैंगे जाणु सारे देश की आफत इसपै आरी सै। मजाक कर ले तो सिर पै आवैं। भाई हंसणा-हंसाणा तो आपणी संस्कृति सै। मैं तू न्यूं कहूं हंसी मजाक वाली जो संस्कृति म्हारे हरियाणे की सै वो कितै भी कोन्या। इसलिए तो म्हारे हरियाणे के लोग सेहतमंद होवै सैं। खेलां में और पढ़ाई में आगै रहणे का एक यू भी कारण सै।

-छबीले, यो बात सब जाणै सैं अक हांस हसंकै जीवन काटणा चाहिए। पर के कर्‌या जा। घर गृहस्थी में यू इतणा आसान कोन्या। गोज में दो रुपए ना हों तो टेंशन, बालक ना मानैं तो टेंशन, अड़ौसी-पड़ौसी कुछ कह दे तो टेंशन, घरआली गेल्यां विचार ना मिलैं तो टेंशन। टेंशन की वैराइटियां का के तोड़ा सै।

-एक बात और रसीले, जिसका गुजारा ठीक चालर्‌या सै वे भी टेंशन में रहै सैं। जिस धोरै गाडी-घोड़े सैं उनकै भी टेंशन और जिस धोरै साइकिल बी कोन्या उसनै भी टेंशन।

- छबीले। आपणा-आपणा जीणे का ढंग हो सै। एक बात मैं डंके की चोट पै कह सकूं सूं। देख यो घर गृहस्थी तो कदे तै न्यूए चालती आई और चालती रहैंगी। जै एक पीढ़ी नै जीणे का तौर तरीका बदल लिया, यानी चाहे किसी बी परिस्थिति हो, हांस बोलकै रहणा सीख लिया। तो उसकी आगली पीढ़ी भी उसीए त्यार होवैगी। हांस बोलकै जीणके के संस्कार बणज्यांगे। और जिननै परेशान रहण की आदत गेर ली तो उस परिवार की कोई गारंटी कोन्या अक आगली पीढी खुश मिजाज रहैगी, बेशक उनके धोरै सब कुछ हो। शिकायत करण की आदत होगी वो फिर वा लंबे समय तक परेशान करै सै।

-तो भाई रसीले हाम सबनै मिलकै रहण चाहिए, एक दूसरे तैं ईर्ष्या करण की बजाय मदद करणी चाहिए।

-सब तो बड़ी बात हांसणा जरुर सै। हांसे तै सेहत ठीक रहै सै। डाक्टर बतावैं सैं अक हंसणे तै शरीर की सारी मांसपेशियां की कसरत होज्या सै और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ै सै। यो चीज बढगी तो फेर कोरोना भी कोन्या होवै।

-रसीले, यो हांसण की नियामत भगवान नै केवल आदमी तै दी है। जानवरां तैं कोन्या दी। इसलिए हांसण का मौका नहीं चूकणा चाहिए। बहुत से लोग तो इसे सैं अक उननै न्यूए नहीं बेरा अक वे खुलकै कद हांसे थे। व्यस्त जीवन और एक दूसरे तैं ईर्ष्या भाव में हांसणा भूलगे।

-भाई छबीले, घणे माणस तो गुदगुदी करे तैं भी कोन्या हांसते। टेंशन के इस चक्र में फेर कदे ही ओल्ले होज्या सै। मैं तो न्यू कहूं सूं भाई, जिसी रोटी मिलज्यां उसी खाल्यो। मरोड़ मत करो, वरना मरोड़ कै करोड़ लाग्या करैं।

- हां भाई माणस नै घणे चक्करां में पड़ण की कोई जरुरत कोन्या। कोई बालक मानैं तो ठीक, ना मानैं तो ठीक। और फेर कुदरत नै सबकी शक्ल अलग-अलग दी सै, तो दिमाग भी अलग अलग दिया सै। जिब शक्ल ए ना मिलती तो दिमाग क्यूकर मिलज्यागा? सबकी सोच अलग होगी। यो फर्क इंसान के हाथ में कोन्या। और जो चीज इंसान के हाथ में ना हो, उसके बारे में चिंता करकै सेहत खराब नहीं करणी चाहिए। मेहनत करो और खुश रहो। हंसते और हंसाते रहो।

-मनोज प्रभाकर

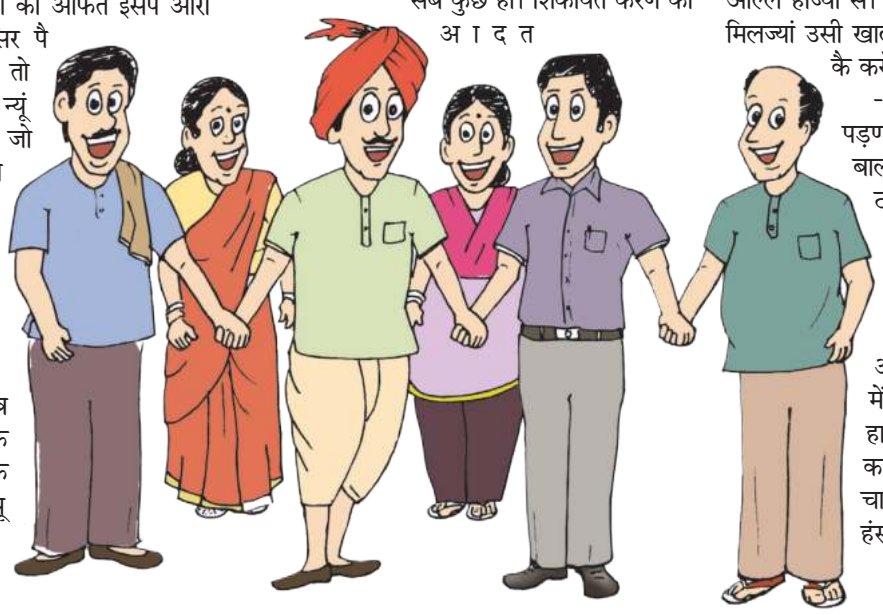

सच मानो भगवान है

माँ

माँ सच्ची करतार है।
माँ ही रचनाकार है।
माँ ममता की छाँव है,
माँ सच्ची दातार है।
रोते को भी हंसाये माँ।
मुझको खूब खिलाये माँ।
खुद गीले में सो कर,
सूखे में मुझे सुलाये माँ।
माँ ही पालनहार है।
माँ देती प्यार दुलार है।
अमृत पान कराती है,
माँ सुखों का भंडार है।
माँ मेरा सम्मान है।
माँ मेरी मुस्कान है।
माँ ही इस संसार में,
सच मानो भगवान है।

-भूपसिंह भारती

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com